an>

Title: Further discussion regarding need to have stringent legislation to check increasing atrocities against women and children in the country rasied by shri P. Karunakaran on the 6th August, 2014 (Discussion concluded).

*__श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):__ नियम 193 के तहत् महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ रहे अत्याचारों की रोकथाम करने के लिए भारतीय संसद में निर्भया कांड के बाद बहुत बड़ा कानून बनाया गया , लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं के प्रति अत्याचार थमने का या कम होने का नाम नहीं ले रहा है। समाचार पत्रों में आये दिन महिलाओं के प्रति अत्याचार के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण शिक्षा के साथ संस्कारों की कमी है। वर्तमान में जो शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है उससे चरित्र निर्माण और संस्कार निर्माण के क्षेत्र में बहुत कम संस्कार स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को दिये जा रहे हैं और संस्कार निर्माण का महत्वपूर्ण स्थान स्कूल ही होता है। घरो में भी बच्चों को संस्कार निर्माण का अवसर नहीं मिलता है क्योंकि बच्चों के मां-बाप अलग काम में बिजी रहते हैं और बच्चे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से संस्कार निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्य में बिजी रहते हैं, जिससे संस्कार निर्माण का क्षेत्र उपेक्षित हो गया है। समाज में साधु-संतों के माध्यम से जो संस्कार निर्माण या जो चरित्र निर्माण का कार्य कराया जाता है, उसमें भी बहुत कमी आई है। इससे इन परिस्थितियों में मेरा यह मानना है कि जब तक संस्कार निर्माण और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में बहुत समुचित ढंग से कार्य सम्पादित नहीं किया जायेगा और नैतिकता का विकास समाज में नहीं किया जायेगा तब तक मात्र कानून से ही महिलाओं पर अत्याचार रूक जायेगा, ऐसी संभावना कम है। उनके दहेज के विरोध में शारदा एक्ट वर्षो से हैं, लेकिन फिर भी दहेज की खबरें आये दिन अखबारों में प्रकाशित होती हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कानून बन गये हैं, लेकिन इसके बावजूद उन क्षेत्रों में अपराध कम नहीं होते हैं। बच्चों के प्रति जो अपराध गठित हो रहे हैं, उनमें भी एक अध्ययन से ये जानकारी मिली है कि परिवारों और उनके साथ बच्चों के प्रति गठित अपराध ज्यादा करते हैं। इसमें यौन शोषण के अपराध भी सम्मिलित हैं। अतः इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवार, समाज और स्कूली शिक्षा द्वारा संस्कार निर्माण और चरित्र निर्माण की शिक्षा उपलब्ध कराकर समाज और देश में नैतिकता का विकास करना अति आवश्यक है और इससे ही महिलाओं एवं बच्चों पर अत्याचार की घटनाओं में कमी आयेगी।

कानून बनाने के बाद उसकी अनुपालना होती है, उसका मॉनिटरिंग सिस्टम भी देश में कमज़ोर है। इसलिए कड़े नियमों के साथ कानून की पालना तथा मॉनिटरिंग सिस्टम किये जाने की जरूरत है और जो लोग कानून की पालना की अनदेखी करते हैं उनके खिलाफ सजा एक नियमित अवधि में शामिल होनी चाहिए। जिससे कानून का डर भी अपराधों को रोक सकता है अभी कानूनों का डर नहीं होने से कानून होते हुए भी अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

*__SHRIMATI K. MARGATHAM (KANCHEEPURAM):__ Before I begin my maiden speech in this august House, I would like to thank the Chief

Minister of Tamil Nadu, Hon'ble Amma for this opportunity to participate in debates and discussions and to voice the grievances of the people.

As we all know, it is in our tradition to address 'our country, the rivers and mountains', in feminine gender. Extending this further, I say that the women of India should be respected and given prominent position, and also due regards.

But what are we seeing in the country presently? More and more crimes are being committed against women and children. The National Crime Records Bureau report confirms that they are really on the rise.

The Union Ministry of Women and Child Development runs schemes like Integrated Child Development Scheme, Nutrition Programme for Adolescent Girls, National Creche Scheme for the Children of Working Mothers, Integretated Programme for Street Children, and the others. Moreover, this Ministry is supposed to take care of women and children who account for 70% of our population. But in terms of money allocation in the Budget, it is very meagre.

Coming to the female sex ratio, it is declining in India. But interestingly, the records of census show that in Tamil Nadu, the female sex ratio has increased from 986 to 996 girls to 1,000 males. This is due to the efforts taken by the Chief Minister of Tamil Nadu in protecting the girls. Hon'ble Amma is constantly taking efforts for the welfare of women and girl children. The Cradle Scheme is a grand success in Tamil Nadu and female foeticide has been completely stopped. Women are being helped by the Tamil Nadu Govt. during their pregnancy and during lactating period. The graduate-girls are being given Rs. 50,000 at the time of marriage along with 4 grams of gold. For the working women, Hon'ble Amma has constructed 20 working women hostels.

As per the UN Report, Tamil Nadu is one of the three Indian States which has achieved the Millennium Development Goals, whereas as a country, India has failed. This amply shows the efforts taken by the Tamil Nadu Govt. under Dr. Amma.

In Delhi, a few years back, we had the gruesome rape-cum-murder of Nirbhaya. It was very widely reported that the juvenile who was instrumental in her death, has escaped the law. Here, the silver lining is that the Hon'ble Minister is in favour of bringing a law to treat such juveniles as adults. It is a very welcome initiative and it would act as a deterrent. Secondly, the UPA Govt. has constituted Nirbhaya Fund, which is un-utilized. I request the Minister to utilize that fund for the welfare of women and children.

In India, we have adequate laws, but the implementation is very weak and ineffective. In the case of Tamil Nadu, our Chief Minister is initiating action to book such culprits under the Goondas Act. This would act as a severe punishment. There is a need to have such effective provisions, if we intend to stop such atrocities. I hope that the Hon'ble Minister will initiate such actions that are necessary to stop crimes and atrocities against women and children in this country.

*__श्रीमती प्रियंका सिंह रावत (बाराबंकी):__ आज देश के समक्ष अनेक बड़ी समस्याएं और चुनौतियां हैं उनमें सबसे प्रमुख चुनौती महिलाओं के प्रति बढ़ रहा अत्याचार और उनका शोषण है। शोषण और अत्याचार का कोई स्वरूप नहीं है बल्कि इसके अनेक स्वरूप हैं, जैसे- दहेज के लिए महिलाओं पर हो रहा अत्याचार; बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार; लड़कियों और महिलाओं पर तेजाब फेंकना; ऑनर किलिंग; लड़कियों और महिलाओं की खरीद बिक्री और जबरन वेश्यावृत्ति; तथा घरेलू हिंसा।

हमारे देश का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। हमारे धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में महिलाओं को पुरूषों के समक्ष बराबर का दर्जा दिया गया है और यहां तक कि कई स्थानों पर तो उन्हें पुरूषों से भी ऊपर स्थान दिया गया है। किन्तु आज हम देखते हैं कि प्रत्येक महिला कहीं न कहीं किसी प्रकार से प्रताड़ित हो रही है। मैं नहीं कहती कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और शोषण के लिए पुरूष ही दोषी है, इसके लिए कुछ हद तक महिला भी दोषी है। बहू पर सास द्वारा शोषण इसका उदाहरण है। फिर भी महिलाओं के शोषण में पुरूष का बड़ा हाथ है।

महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को अगर आंकड़ों के नज़रिये से देखें तो हम पाते हैं कि प्रत्येक 3 मिनट में एक महिला के साथ अत्याचार होता है। इसी प्रकार प्रत्येक 29 मिनट में किसी न किसी महिला के साथ रेप की घटना घटित होती है। National Crime Records Bureau of India के आंकड़े भी बताते हैं कि

देश में महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अत्याचार की घटनाओं में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है। Bureau के अनुसार वर्ष 2011 के मुकाबले वर्ष 2013 में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 में कुछ घटनाओं की संख्या जहाँ 2,28,638 थी, वहीं 2012 में बढ़कर 2,44,638 हो गयी। ये सरकारी आंकड़ें हैं जो हकीकत का एक पहलू हैं जबकि स्थिति और भी भयानक है। अनेकों मामले हैं जो या तो दर्ज नहीं कराए जाते या किसी न किसी दबाव के चलते वापस ले लिये जाते हैं।

महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं। महिलाओं में साक्षरता का अभाव, कुपोषण, स्त्री-पुरूष असमानता, हाल के दिनों में आया सूनापन जैसे कारण हैं।

किन्तु सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार का क्या रोल होना चाहिए। क्या सरकार जो कर रही है उस पर संतोष करके बैठ जाना चाहिए या उससे बढ़कर महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों को रोकना चाहिए, उत्तर सबको पता है। यहां सरकार की बड़ी भूमिका है। हालांकि सरकार ने आज़ादी के बाद से अनेक कदम उठाए हैं जिसमें सबसे पहले महिलाओं के कल्याण पर ध्यान दिया गया, तत्पश्चात् उनके आर्थिक विकास पर और हाल के दिनों में महिला सशक्तीकरण पर। सरकार ने महिलाओं के लिए एक मंत्रालय खोला, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अनेक कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाएं चल रही हैं। इन सबका नतीजा सकारात्मक रहा है और महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार आया है, किंतु मूल प्रश्न है महिला सशक्तीकरण का।

एक महिला तभी सशक्त मानी जायेगी जब वह यह निर्णय कर सके कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। इतना ही नहीं अगर एक महिला अपने लिए हुए निर्णय को लागू करवाने में सक्षम होती है या अपने विरूद्ध किए जा रहे निर्णय को रोक पाने में सक्षम है तो मैं मानूंगी कि वह महिला सशक्त है। जब तक महिला के सन्दर्भ में उसके अच्छे या बुरे का निर्णय कोई और लेगा तब तक महिला सक्षम नहीं मानी जा सकती, भले ही एक महिला कितनी ही पढ़ी-लिखी हो और कितना ही सम्पन्न हो, किंतु यदि उसे निर्णय की आज़ादी नहीं है तो वह सक्षम नहीं कहलायेगी।

1993 में देश में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, तत्पश्चात् 33औ आरक्षण की वजह से निर्णय निर्माण में लाखों महिलाएं घरों से निकल कर आगे आयी। आज उसका परिणाम भी आने लगा है, किंतु देश की संसद और विधान सभाओं में आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा ही बनकर रह गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर सख्ती से रोक लगाएं, लोगों में जागरूकता बढ़ाएं, महिलाओं को इतना सक्षम बनाया जाए कि वे खुद अपना निर्णय ले सकें, इसके लिए महिलाओं को 33औ आरक्षण विधायिकाओं में नहीं बल्कि प्रशासन में भी दिया जाए।

***श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा):** आशा बहू एक घरेलू सामाजिक महिला है जो एन.एच.आर.एम.(राष्ट्रीय कार्यक्रम) के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक 500 की न्यूनतम आबादी पर चयनित की जाती है। इनका कार्य समाज के बच्चों तथा महिलाओं को विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना जैसे- टीकाकरण, आयरन की गोलियां वितरित करना, मोतियाबिन्द का ऑपरेशन, प्रसव आदि में सहयोग करना आदि ऐसे कार्य जो घरेलू महिलाओं के सीधे स्वास्थ्य सेवाएं व साथ-साथ सामाजिक रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाती है।

इन सब के बदले में उन्हें पारिश्रमिक कार्य के अनुसार काफी कम 50, 199 या 200 रूपये ही मिलते हैं जिससे इनका उत्साह प्रभावी नहीं रह पाता है

ऐसी स्थिति में एक निश्चित मानदेय देना उचित होगा, जिससे इनका मनोबल व आत्मविश्वास बढ़े और कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी हो। ऐसा करने से हम अपने बच्चों व महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा के साथ-साथ रहन-सहन व सामाजिक स्तर में भी बदलाव कर सकते हैं।

***श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत):** वर्तमान सरकार ने अपने बजट में महिला सुरक्षा एवं महिला विकास विषयों पर भी ध्यान दिया है। देश में महिला अत्याचार संबंधित मामलों पर यह सदन चिंता व्यक्त कर रहा है। महिला अत्याचार की घटना देश को शर्मसार करती हैं। कई बार हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि भारतीय संस्कृति जो कि दुर्गा, सीता, सरस्वती से पहचानी जाती है उस देश में ऐसी घटनायें चिंता का विषय बन रही है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है " यत्र नार्यस्तु पुजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः ", जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवता भी वास करते हैं।

इन कुछ दिनों में घटित घटनाओं में एक और चिंतित करने वाली बात सामने आई है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का इन जघन्य अत्याचारों में लिप्त होना। मेरा सरकार को सूचित करना है कि ऐसे अपराधों में जिनकी जिम्मेदारी रक्षा की है वे या तो सरकारी कमचारी अगर भक्षक बनते पाये गये, उनकी पूरी सर्विस की जो भी जमा पूंजी सरकार के पास है, चाहे वह प्रोविडंड फंड हो, ग्रेच्युटी फंड हो, पेंशन फंड हो, वे सब पीड़ित परिवार को दे दिया जाये। यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति ऐसी घटनाओं में लिप्त पाया गया तो इस राशि को आधा कर दिया जाये। ताकि इनकी जिम्मेदारी जो रक्षक की है वह भक्षक न बनने पाये। ऐसे मामलों में पुलिस कार्यवाही में देरी के जो भी कारण हैं, उनका पूरा ब्यौरा पुलिस डायरी एवं एफ.आई.आर. में लिखना अनिवार्य करना चाहिये कि घटना कब घटी एवं एफ.आइ.आर. कब हुई तथा पुलिस ने कार्यवाही कब शुरू की। आमतौर पर ऐसे केसों में बताया जाता है कि पुलिस कार्रवाई में देरी होने के कारण अपराधी को भागने का मौका मिलता है। वह मौका न मिल पाये एवं न्याय मिलने में जल्दी हो। 2014 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर धन देकर निर्भया फंड का उचित उपयोग पीड़ितों को मदद देकर, फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वारा त्वरित न्याय देने का प्राविधान किया है, जो स्वागतयोग्य है।

इस विषय में गुजरात में महिला सुरक्षा विषय को जिस तरह से सरकार द्वारा हाथ में लिया गया है, उसी तर्ज पर केन्द्र सरकार भी योजना बनाये, ऐसी मेरी मांग है। मैं गुजरात की माननीय मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल द्वारा इस विषय को जिस गंभीरता से हाथ में लिया गया है, उसकी भी सराहना करती हूँ। उनके द्वारा पदग्रहण करने के बाद प्रस्तुत किये गये पहले बजट में गुजरात में कई नये कदम उठाये गये हैं। गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री माननीय आनंदी बहन ने जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करके जेन्डर बजट के माध्यम से महिलाओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। स्व-सुरक्षा की जागृति लाने हेतु पुलिस डिपार्टमेंट और एन.जी.ओ. के साथ मिलकर महिलाओं को स्व-सुरक्षा के क्षेत्र में शिक्षित किया है। पुलिस महकमे में 33 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मचारियों की भर्ती करने का नियम बनाकर इस कार्यक्रम में महिलाओं को जोड़ा है। एन.सी.सी., महिला सुरक्षा समिति, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा महिलाओं की पुलिस भर्ती ट्रेनिंग, पुलिस को बातमी देना, मदद करना जैसे बहादुरीपूर्ण कार्य करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन देकर उनको सशक्त किया है। गुजरात सरकार ने 1 से 15 अगस्त के बीच महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तीकरण का पूरे राज्य भर में कार्यक्रम घोषित किया है। गुजरात सरकार ने चुनाव पंच को भी सुझाव दिया है। जिसके घर में शौचालय न हो वह सरपंच से लेकर तालुका जिला पंचायत तक चुनाव नहीं लड़ पायेंगे, क्योंकि ज्यादातर घटनाओं में घर में शौचालय न होने की वजह से रात को अकेली बहन, बेटी पर जघन्य घटना होती है।

इसी मंत्रालय से जुड़ा प्रश्न है, बाल मजदूरी। यह भी हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं जानना चाहूंगी की पिछले पांच सालो में देश में बाल मजदूरी के कितने केसेस पाये गये और कितने बच्चों को छुड़ाया गया? जिन बच्चों को छुड़ाया गया, वे आज कहां पर हैं और उनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? मेरा आग्रह है कि जिन जगहों से इस प्रकार के बाल मजदूर पकड़े जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उन प्रतिष्ठानों को जो भी राहत सरकार से मिल रही है, उनको तत्काल रोक दिया जाये। जैसे कि ऐसे प्रतिष्ठानों को भारत का राष्ट्रीय कानून भंग करने की सजा के रूप में उनको मिलने वाली इन्कम टैक्स बगैरह की छूट को रद्द कर देना चाहिए, ताकि कानून का भय अपराधियों के ऊपर रहे।

जैसे पुलिस प्रशासन में 33 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती, सेल्फ डिफेन्स की 15 दिनों की ट्रेनिंग, पूरे राज्य में बहन, बेटियों को मिले, उसके लिए अलग से बजट का आवंटन हो, जिन महिलाओं द्वारा इस प्रकार के गुनाहों को रोकने के लिए कुछ भी कार्य किया है, उनका सम्मान जैसे कार्य प्रमुख हैं। मान्यवर गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव आयोग से एक और गुजारिश की गई है। आमतौर पर गांवों में घर में शौचालय न होने की वजह से बहन, बेटियों को घर से बाहर ऐसी क्रियाओं के लिए जाना पड़ता है। उसका लाभ असामाजिक तत्वों द्वारा उठाया जाता है। उन्होंने आयोग से मांग की है कि हर घर में शौचालय की व्यवस्था जहां पर न हो उस गांव के सरपंच, प्रधान को इसके लिए जिम्मेदार मानना चाहिये और वह चुनाव आगे चलकर न लड़ पाये, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ऐसे मामलों को संवदेनशीलता से हाथ में ले रही है। यह चर्चा उसी का परिणाम है। गुजरात में कार्य करने के लिए सुरक्षा समिति वगैरह की योजना बनाई गई हैं, वह पूरे देश भर में लागू करने के लिए मेरी मांग है। कन्या शिक्षा में स्वरक्षा को भी सम्मिलित करने का मेरा सुझाव है। साथ ही, ऐसे मामलो में फास्टट्रैक कोर्ट की व्यवस्था एवं पीड़ितों का विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोर्ट कार्यवाही में सम्मिलित होना, जैसे उपाय किये जाने चाहिए ताकि पीड़िता एवं उसके परिवार की पहचान छुपाई जा सके। 2014 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर धन देकर निर्भया फंड का उचित उपयोग पीड़ितों को मदद देकर फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वारा जल्दी न्याय देने का प्रावधान किया है, जो स्वागतयोग्य है।

*__श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर):__ भारत में महिलाओं के साथ हो रही बलात्कार की घटनाओं से सम्पूर्ण भारत के साथ ही अमेरिका जैसा देश भी चिंतित है। देशभर में हो हरी बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले ही हैं, दूसरी ओर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की भद्दी-भद्दी टिप्पणियां हैं। जिम्मेदार पदों पर रहे पूर्व में केन्द्रीय कोयला मंत्री जी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री हों या उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री हो, सभी जिम्मेदार लोगों की सोच महिलाओं के प्रति संवेदनहीन होने का नमूना है, किंतु जब सीमा पर जवान शहीद होता है तो कहा जाता है कि धन्य है वो माँ, जिसने इस लाल को जन्म दिया तब अप्रत्यक्ष रूप में स्त्री का ही गुणगान होता है। वैसे भी हमारे भारतीय इतिहास में महान नारियों का योगदान है, जिन्होंने अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता, साहसिक क्षमता और युद्ध कुशलता का परिचय दिया है।

इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ महिला कर्मियों से छेड़छाड़ के मामले में निलम्बित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बदहाली का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आरोपी सिद्ध होने के बाद सजा होने के अनुपात में अन्य मामलों की अपेक्षा बलात्कार की घटनाओं की रफ्तार कम है।

हमारे उत्तर प्रदेश की लड़कियों के साथ बलात्कार करने के बाद पेड़ पर लटका दिया जाता है। बरेली में एक युवती के साथ बलात्कार कर तेजाब पिलाकर पेट्रोल से जलाया जाता है। शाहजहाँपुर में डेढ़ वर्ष पहले पूजा नाम की नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया। पूजा का परिवार कलेक्ट्रेट के सामने तभी से आज तक धरने पर है। इतना ही नहीं शाहजहांपुर में 6 से 13 वर्ष की बालिकाओं के साथ बहुत सारी घटनायें प्रकाश में आयी हैं।

क्रायसिस सेल के अतिरिक्त देश भर में 114 शहरों में तत्काल सहायता पहुँचाने हेतु जी.सी.एस. आधारित सहायता वाहन तैयार किये जाने के साथ ही एकीकृत कम्प्यूटर आधारित प्रेषस प्लेटफॉर्म की भी योजना है जिससे संकट में फंसी महिलाओं को लोकेट किया जा सकेगा। इस योजना से पीड़ित महिला को काफी हद तक बचाया जा सकेगा।

महिला अपराध के साथ ही शोषण का आंकड़ा भी हमारे देश में गंभीर समस्या है। हर साल हज़ारों बच्चे गायब हो जाते हैं। अकेले वर्ष 2013 में 7181 बच्चे गायब हुए जिनमें अभी तक आधे भी जिला प्रशासन द्वारा पता नहीं लगाये जा सके हैं। गायब बच्चों में आधे से ज्यादा लड़कियां हैं।

सूत्र बताते हैं कि मानव तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा दिल्ली के एक इलाके में है। निठारी काण्ड भी एक आश्चर्यचकित उदाहरण है। मैं पुनः अपनी सरकार को बधाई देती हूं जो महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है।

उत्तर प्रदेश में मुजफ्फनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, लखीमपुर, औरेया, फतेहपुर, कानपुर, रामपुर, बहराइच, फिरोजाबाद, कन्नौज आदि जिलों में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध के मामले सामने आते रहे हैं। सदियों से चली आ रही पुरूष प्रधान की मानसिकता भी इसके लिए जिम्मेदार है। महिला को दोयम दर्जे का मानने की मानसिकता भी कम नहीं हो पा रही है। इस मानसिकता को बदलने की शुरूआत मात्र कानून से ही नहीं बल्कि घर परिवार से करनी पड़ेगी। स्त्रियों के साथ मर्यादित व्यवहार करना घर ही से सीखना होगा। साथ ही अपराधी के खिलाफ कार्यवाही कर जल्द से जल्द कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। सजा ऐसी हो, जिसे सोचकर लोगों को डर लगे।

मैं माननीय राजनाथ जी, माननीया मेनका गांधी जी को बधाई देना चाहती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण देश के प्रत्येक जिले में विशेष केन्द्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इस केन्द्र को क्रायसिस सेल के नाम से जाना जायेगा, जिसके अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए एवं संकट में फंसी महिलाओं को तुरंत सहायता पहुंचायी जा सकेगी।

" बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं " पर 100 करोड़ का प्रावधान किया है, जो हमारी सरकार की संवेदनशीलता महिलाओं के प्रति दर्शाता है। अंत में कहना चाहूंगी कि स्त्री और प्रकृति के समतुल्य है, इन दोनों का सम्मान करना ही होगा अन्यथा मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा।

*__श्री पी.पी. चौधरी (पाली):__ एनसीआरबी द्वारा जारी पिछले तीन साल के आंकड़ों ने महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में बताया है कि इनमें लगातार बढ़ोत्तरी हुई है, जो कि इस प्रकार है- 2011 में 2,28,650, 2012 में 2,44,270 एवं 2013 में 3,09,546 अपराध हुए हैं, जो कि हमरे लिए बहुत चिंता का विषय है।

इस विषय पर काफी दिनों से चर्चा हो रही है कि कठोर कानून लाया जाये जिससे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध बढ़ गये हैं, उनको रोका जा सके। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि इस संबंध में देश में कठोर कानून की कोई कमी नहीं है। हाल ही में क्रीमिनल लॉ (अमेंडमेंट एक्ट) 2013 में महिला के खिलाफ अपराधों के मामले में कठोर सजा का प्रावधान रखा गया है। इसमें अगर जरूरत है तो कानून की सही पालना की है।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कई कारण हैं, इसे हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा नगण्य है, गरीबी के कारण और अन्य कई कारणों से प्रांरभिक व माध्यमिक शिक्षा तक भी गांव में महिलायें शिक्षित नहीं हैं। अगर देखा जाये तो उच्च शिक्षा में ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी सिर्फ 9औ है। यही नहीं, आज गांव में महिलाओं के लिए शौचालय का अभाव है और लगभग 70औ लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं, जो कि इस तरह के अपराधों में डर के मारे उन्हें झुण्ड में शौच के लिए जाना पड़ता है। यही नहीं हमारी पुलिस फोर्स में सिर्फ 5औ महिला ही हैं जबकि इनकी भागीदारी लगभग 33औ होनी चाहिए। गांव में जो अपराध होते हैं, उनमें समाज के डर के मारे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाती है। यह सभी कारण अपराध में बढ़ोत्तरी की वजह बनते हैं। अभी हाल में पहली बार हमारे वित्त मंत्री व हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग से निर्भय कोष का प्रावधान रखा है, जिसमें पहली बार 150 करोड़ रूपये चयनित जिलों के लिए रखे गये हैं, जिससे अगर महिलायें तकलीफ में हों तो ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा उनको राहत पहुंचाई जाये। यही नहीं हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने 2014-15 के बजट में बच्चों के विकास के लिए 81075 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। इसमें 18,691 करोड़ रूपए इंटीग्रेटिड चाइल्ड डेपलपमेंट, 100 करोड़ रूपए " बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ " के लिए, 715 करोड़ रूपए नेशनल मिशन फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन और 400 करोड़ रूपए इंटीग्रेटिड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के लिए रखे गये हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित है।

जिस तरह के महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए उपाय सोचे जाने चाहिए। अगर अपराध घटित भी हो जायें तो उसमें पीड़ित को शीघ्र सहायता पहुंचाने के लिए भी उपाय सोचे जाने चाहिए। आज की तारीख में जब अपराध घटित होता है तो सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अपराध की जांच करने वाली एजेंसी, जो पुलिस फोर्स हैं, वह पूर्ण रूप से इक्विप नहीं होने की वजह से जांच में कई तरह की खामियां रहती हैं। जांच में खामियां रहने के और कई तरह के कारण हैं, जिसका विवरण मैं नहीं देना चाहूंगा। न्यायालय में ज्यादातर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में प्रोसीक्यूशन द्वारा जांच सही नहीं करने व पक्ष नहीं रखने की वजह से ज्यादातर अपराधी छूट जाते हैं। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि अपराध की जांच प्रोसीक्यूशन व अपराध में एक्सपर्ट अधिकारियों द्वारा ही करवायी जानी चाहिए, जिससे आज की तारीख में जो 90औ अपराध में दोषमुक्ति होती है, उससे निज़ात पाई जा सके। यही नहीं, महिलाओं और बच्चों के अपराध के संबंध में स्पेशल न्यायालयों का गठन हो, जिससे तीव्र गति से न्याय हों, जिससे आमजन में कानून के प्रति विश्वास भी पैदा होगा व अपराधी के मन में यह डर भी रहेगा कि उसे सजा अवश्य मिलेगी।

आज की तारीख में बालिकायें जो हैं वह एक बोझ की तरह मानी जाती हैं, जिसकी वजह से आज पुरूष एवं स्त्री का अनुपात जो है, 2011 के सेंसेक्स के अनुसार 1000 पुरूषों पर 914 महिलायें हैं, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय ही नहीं अपितु एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज देश में भ्रूण हत्याओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। 1600 भ्रूण हत्या प्रतिदिन होती है इसलिए हमें पीसीपी एक्ट में उचित संशोधन की आवश्यकता है।

जहां तक बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले हैं वह हमसे छुपे हुए नहीं हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि लगभग 1 लाख बच्चे प्रतिवर्ष गायब रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में सालाना रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, इसको हमें गंभीरता से लेना होगा।

अतः सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध में कमी लाने के लिए उचित उपाय किये जाने चाहिए।

*__श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर):__ मैं एक उदाहरण के उल्लेख के साथ अपनी बात प्रांरभ करना चाहूंगी कि हरियाणा के भगाणा गाँव की दुष्कर्म पीड़ित 4 बच्चियां कई दिनों से लगातार सत्ता के इस मंदिर से चंद मिनटों की दूरी पर जंतर-मंतर पर इस आशा में बैठी हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। यह वही स्थान है जहां दिसंबर की ठंड में लोगों ने निर्भया के लिए इंसाफ मांगा था। कई कड़े कानून बने, क्योंकि सरकार हरकत में आई, लेकिन फिर ठीक उसी जगह 4 और निर्भया बैठने को विवश है क्यों?

क्या सवाल वाकई कड़े कानून बनाने का है? या फिर सवाल ये है कि तमाम कड़े कानून बनकर भी लागू नहीं हो पाते और महिलाओं पर अत्याचार करने वाले अपराधियों के मन में कानून का खौफ नहीं है और विशेषकर से जब पीड़िता समाज के वंचित दलित पिछड़े आदिवासी तबके से आती हो, जो जातिवादी और सामन्तवादी मानसिकता की शिकार हो और अक्सर जिसके प्रति लोकतंत्र के चार खम्भों का व्यवहार भी अलग किस्म का हो, तो यह कानून का भय और भी नगण्य हो जाता है।

पुलिस-प्रशासन के लचर रवैये के चलते अधिकांश मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं। अत्याचार की भुक्तभोगी महिलाएं हिम्मत जुटाकर यदि थाने पहुंचती हैं तो उन्हें सहानुभूति के स्थान पर दुत्कार,अपमान व उपहास ही मिलता है और जो मामले दर्ज हो भी जाते हैं तो उनकी कोर्ट में सुनवाई कई वर्षों तक चलती रहती है। पूरा मामला तारीखों में सिमट कर रह जाता है।

क्या फास्टट्रैक कोर्ट सचमुच फास्ट काम कर पा रही है? जिससे अपराधी के मन में खौफ पैदा हो। कुछ ऐसी ही स्थिति बाल उत्पीड़न के मामलों की भी है। 5-12 वर्ष की उम्र के बच्चों पर सर्वाधिक अत्याचार होता है। बच्चों के शोषण के अधिकांश मामलों का भी समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा है। जिसके फलस्वरूप घटनाओं की संख्या में गिरावट नहीं आ रही है।

सरकार ने 2012 में बच्चों की सुरक्षा के लिए POSCO अर्थात् Protection of Children Against Sexual Offences एक्ट बना ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो सके, लेकिन कानून लागू होने की तिथि से लेकर 2013, सितम्बर तक महज साढ़े पांच फीसदी मामलों का ही निपटारा हो सका और केवल 14 आरापियों को ही दोषी करार दिया गया।

इतना ही नहीं इस कानून में केवल 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, जिसके चलते भी अपराधी के मन में कानून का भय पैदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए और कड़े प्रावधान करने और समय से निपटारा करना जरूरी है।

*SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): This august House had discussed this matter in the last Lok Sabha consequent to the public outrage after the horrifying gang rape committed on a hapless girl who was on her way back to home in December 2012 in the capital city of Delhi. This horrendous incident along with other instances of rape and atrocities on women and children had evoked great amount of rancor among the people across the country.

In order to give teeth to the existing laws, this august House, in its wisdom, had decided to bring about drastic amendments in the criminal laws. The House has passed the Criminal Law (Amendment) Act unanimously. The intent of this amendment is widely lauded but it is saddening to note that it has failed to stem the tide of violence.

It is agonizing to note that females are targeted everywhere, whether it be at the schools, colleges, work places, streets, buses and even at public functions and at their own homes. It is also astounding to observe that more than 90% of the rapes are by relatives, friends or acquaintances and it mostly takes places in or near the houses where the victims stay.

In a male dominated society known for its notorious caste, communal, gender and parochial mindset one would expect even worse.

At the outset, I wish to place on record that it is not dearth of adequate laws that stand in the way of containing offences against women and children. It is mindset and attitude that must undergo rapid transformation. Therefore my initial observation is that we should take up this as a challenge to a civilized society and utmost vigilance is to be exercised by the community at large. What is required is to arouse the collective conscience of the society.

As the saying goes "charity begins at home" and lessons relating to values and morals should also start from every household. I underscore the importance of moral education to children right from pre-primary stage itself. Unfortunately such a system is not in vogue in our educational system and adequate changes must be brought in the syllabus. We need not wait until a judicial pronouncement is made in this regard. This House can debate this issue in the spirit of co-operative federalism and direct the state governments to do the needful accordingly.

Education is the most effective vehicle that can bring about social transformation and it is in the classrooms that the seeds of values are sown and grown.

Our rich cultural heritage has taught us to adore women and give utmost affection to children. But what is now happening in the country is deeply disturbing as also most reprehensible. No day passes without reports relating to gory rape, molestation, attacks and atrocities against women and children.

Human right organizations and World Watch groups look at our country with utter contempt and disgust.

Gender discrimination is prevalent in many parts of the country and attack and atrocities committed on the women and girls are astonishingly on the rise. We should all hang our heads in the shame that female foeticide is still in vogue in our country. Not only this, our society also discriminates against women and penalizes them at the community level. Dowry death and honor killing are also prevalent.

With the advancement of technology we have access to internet and the most sophisticated means of communication. Easy access to these is exposing young minds to the worst forms of pornography, sexual abuse and the most vulgar perversions. Here, parents need to be sensitized on the evil effect of these modern social media.

The impact of this definitely vitiates the young minds. In the infamous Delhi gang rape case a seventeen year old boy is one of the accused. This is not an isolate incident. There are a large number of instances where juveniles are involved in rapes and other heinous crimes. In many cases the argument of being juvenile is an escape route for the perpetrators of horrendous crimes.

Hence, the demand to revisit the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 cannot be brushed aside.

There are reports that many of our tourists centres are infested with pedophiles. This issue is to be addressed as children from poor families are being lured into sex at early age.

It is a well known fact that instead of supporting the victims the predators are often being protected. Law enforcing agencies, especially the police have a formidable role to play in checking the crimes and atrocities against women and children.

There are allegations against the complicity and negligence of the police. The fact remains that colonial mindset of some policemen often leads to insensitivity and indifference when crime is committed on women and children has taken place in the attitude of the police after the Nirbhaya case.

Since the present criminal law is stringent, victims and their families come forward to register their cases with the police.

The demand for Police Reforms is long pending and time has come for us to bring in drastic reforms in the police system. As part of the police reforms it is incumbent on the Govt. to reserve minimum 30% posts in the police forces for women. This will definitely instill confidence and faith in the police.

We need to take immediate steps to combat gender based violence and improve safety of women, girls and children in our country.

The tormented females undergo a great amount of emotional trauma and psychological support and counseling are to be provided to the victims.

Civil society groups, youths, women's organizations, political denominations, etc. have a critical role to play in combating the crime against women and children.

The steps initiated by the Ministry of Women and Child Development, as mentioned in the communication of the hon'ble Minister, dated 26th June 2014, is indeed a step in the right direction. The 'Rape Crisis Centre' and the proposed facilities like helpline, first aid/medical help, assistance in lodging FIR, psycho counseling and legal aid etc. are all absolutely essential. But more remains to be done in changing the mindset of the perpetrators as also the attitude of the society.

Before I conclude, I urge upon the Govt. to bring about early legislation for increased reservation for women in Parliament and Legislative

Assemblies. Representation to local body is also to be enhanced. Without empowerment of women it is hardly possible for us to attain our goal of gender equality and contain atrocities and violence against women and children. Therefore, what is necessary is empowerment of women at all levels of our society.

*SHRIMATI RITA TARAI (JAJPUR): We all know that women have always been at the receiving end in our society, especially in India. Women's status is regarded inferior to their male counterpart. The birth of a girl-child has always been treated with sympathy and not with what she deserves. When the family welcomes the male-child with celebrations, the girl-child is neglected right from birth. While rearing the child, there is always a bias against the girl-child. The family gives priority to the education of the boy rather than the girl. Despite all discriminations, if a girl manages to study well, she is deprived of the right to education and more so to the higher education. Parents marry her off at the first available opportunity and treat her as a burden. She gets saddled with early pregnancy and motherhood. She hardly gets any nutritious food for sustenance. She just survives like a pitiable creature in misery.

Atrocities on women in our country have become so common these days that everyday newspaper without exception have numerous reports on female-foeticide, physical violence, abuse, rape, molestation, dowry and death and so on. Women are not safe anywhere. They become the subject of eve-teasing that is more common in the public transport, they get harassed in office, exploited in hostels, are attacked with acid and are burned to death for dowry.

Our is a male-dominated society. Here the women's voices always are made to drown. The decay in moral values and a consumerist culture have projected women as objects of derive. They are assaulted in full public view and also in public places. The most horrible case of 'Nirbhaya' is a case in point. It's tragedy that its culprits are yet to be punished. The judicial process in our country is too slow, where the justice-seeker has to wait a lifetime to get the verdict. Police stations too are not women-friendly. The atmosphere in a police-station is so hostile and anti-women that a female hesitates to go there.

Therefore, there is an urgent need to appoint more and more female personnel in a police station so that the victim would feel safe and can confide in to female officers. I want to congratulate Madam Maneka Gandhi who has taken steps to bring the offending Juveniles to book.

All of us here are representatives of the people. Let us all promise that in our constituencies we will open at least one primary and one secondary girl schools, as the education is an important tool that will empower girls, females and women at large. The government must at a policy level decide to appoint maximum numbers of female-teachers in schools and colleges. Every political party should ensure that at least 50 percent seats are given to female candidates. In all State Legislative Assemblies, Lok Sabha and Rajya Sabha, 50 percent reservation for women should become a reality. Women are an essential and beautiful part of this world. Let us all work to make them feel, safe, secure and strong.

*SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): I humbly submit my profound thanks to the TAMIL NADU CHIEF MINISTER Hon'ble PURATCHI THALAIVI AMMA for being given me an opportunity to be a Parliamentarian in this Hon'ble House.

Women should be given priority in Society and their liberty should not be deprived of. By giving much importance to the woman and child the Tamil Nadu State Government headed by our Hon'ble Chief Minister Puratchithalaivi Amma has implemented several Welfare Schemes for them from craddle to marriage.

Women is being taken care of from pregnancy to till she gives birth to the baby. After that child is being taken care of by providing immunization to the child. After that they are being taken care of through Aganwadi till they join elementary Schools and continuing till their school or college level. During their education till High School level, they are provided food through Noon Meal Programme as also subject books/notebooks. Surrounding village level students are provided with bicycles. College level students are provided with Laptop and Computers. Subsequently, for female students who have studied upto 10^{th} as well as Degree level, their parents are being helped financially as well as sentimentally.

Emotional abuse is the act of causing harm to the development of a child. It is a raising concern in India is they could not perform well in school and college examinations.

Sexually abuse is engaging child to a sexual activity, conducted by an adult or another child who is developmentally superior to the victim.

In the case of female children they are being abused physically as well as sexually on the streets as also at schools, orphanages, residential homes, in the work places etc., many times with violence. Because of this, the normal development of these children will be affected mentally and as a social being, sometimes this will lead to end their life. These are all done by the people who are having frustrated mentality cultivated from the early of their lifestyle. These all happen only because of their parents neglect these persons.

Hence the women is playing an important role in our society, they should be given proper education and counseling by parents and their teachers at all levels. Social awareness should be created from the root level among women to inculcate good knowledge, good physique and morality in their children's mind through Anganwadi, Primary Health staff as well as elementary school teachers.

Despite the fact that in very many States in India we have news relating to the sexual abuse against female children and woman folk very frequently, these cause concern to the government.

To curtail this menace our Chief Minister Puratchi Amma had already taken stringent measures to deal with severely and put the offenders behind bars in Tamilnadu.

The same kind of policing against atrocity against woman and sexual abuse towards female children is needed to stop.

Thank you once again for having given an opportunity to place my views in the honourable House.

*DR. MUMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Autocracy, male dominance and sexual harassment on women are running through ages and throughout the world. Women are vulnerable from womb to tomb. Unfortunately, India is coming in forefront in this matter in recent years and declared a hazardous place for women. Ironically, Indian religious majorities worship many female Devatas but autocratic behaviour, violence and sexual assaults are showing increasing trends. There is female foeticide, infanticide, child sexual abuse and neglect, physical and mental torture in the form of assaults, beating up, murder (including dowry death and honour killings), compelling to be Sati and sexual assaults (rape and gang rape) which has no bar of age (from child to senior citizen)

Recently, there is slight decrease in the rate of infanticide which may be because females are not allowed to be born at all; the story of missing girls' . Due to misuse of scientific advancement and sex determination process female fetus are aborted. This leads to alteration of sex ratio and disturbing eco balance of human race.

It is a shame that this particular problem is basically in India, no other country in the world is having this. This is more pronounced in Punjab, Haryana, UP, Bihar is no bar and is now spreading in other states also. The incidence is least among tribals, christians comes next, then muslims. It is mostly the disease of affluent classes who can afford sex determination tests.

Dowry system was originally in Hindu marriage customs but now it is social disease which has spread to others namely among muslims and Christians also.

Domestic violence and sexual harassment have no bar, be it a cast, social class, creed or religion or educational level or nation. Though it is more profound in low socio economic and higher socioeconomic status and comparatively less among middle class, with emergence of neo-middle class the incidence of sexual harassment (specially gang rapes) and violence and murder is increasing in this class also.

In our country, all these problems are related to socio economic condition, age-old social customs, behaviour and partly lack of political will and effort to solve or eradicate the problem.

Whenever there is dowry death, or rape we think of strengthening the law and some demonstration by women organization etc. and then it gradually dies off and forgotten. Even police is very reluctant to take up the FIR and proceed for action. Domestic violence and similar sort of abuse etc. are hardly reported and even not taken seriously by police.

These problems are far reaching and need multiple longtime action plan. We talk about strengthening the laws. Making legislation itself does not mean anything, it needs proper implementation, administrative power, political will and sincerity in action. Till date there is enough law but none of it has shown to be effective.

Dowry Prohibition Act 1961 amended in 1980, Commission of Sati (Prevention) Act, 1987, Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Indecent Representation of Women (Prohibition Act) 1986, Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 , Child Marriage Prohibition Act, PNDT Act for prevention of female foeticide. For Sexual Assault/rape, there is IPC code 1860.

There are various obstacles to the way of getting justice. Most of the time women are either ashamed or afraid to go to police or to report in official place. Police mindset still favouring men, accuracy, political and other pressures and other illegal behaviours are the impediments.

Basically what is needed in women empowerment in the form of women's education and health is atleast 30 to 40% reservation in all public Representation places like Panchayat, Zila Parishad; Legislative Assembly and Parliament. There should be also proper representation in police and other administration levels.

For domestic violence, female foeticide and dowry death, we need extensive public awareness campaign for domestic violence. The family court should take better initiatives. There should be more family conseling centres to be established. As regards the question of female foeticide public awareness programmes regarding dangers of this trend and its effects on society etc. should be explained.

Our social and moral responsibility towards reducing sexual assault may play a major role. Toilets and electricity in all houses and villages and chowkidars may help in certain extent. Sharp vigilance over night clubs of hotels and amusement places and restriction and proper monitoring of alcohol and similar things should be proper.

Media can play much more role in this matter. TV and other imaging media should restrict, exposing women body in advertising, cinema etc. There should be restriction and strong censor system so that erotic scenes are not shown. Ministry of Information and Broadcasting should take care of it.

People love girl child, fearing their future because of security, dowry and as a depreciating assets. The apathy towards girl child grows. Son will be an earning member, without son there won't be 'Swaragabas'. This sort of believes are the reason behind craving for boy. Empowerment of women would allay this. Girls are now even unsafe in schools. School authorities should take proper security and care of it.

***श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर):** आज देश चिंतित है और चिंता से बाहर निकलने हेतु भी कुछ चिंतित है। महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में पांच टी- ट्रेडिशन, टूरिज्म, टैलेंट, टैक्नोलॉजी और ट्रेज पर जोर दिया, हर हाथ को काम देने का वायदा किया। 2022 तक सबको मकान देने का वायदा किया तो साप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए " जीरो टॉलरेंस " की नीति अपनाने पर बल दिया। भारत में साप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से निपटने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित किये जाने पर आज चर्चा है। यह तंत्र विकसित होने का संकल्प तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में निहित है मगर जब तक व्यक्तियों के मानस में यह संकल्प नहीं आयेगा, सफलता संदिग्ध ही रहेगी। भारत का साप्रदायिक हिंसा से बड़ा पुराना नाता है। देश में सब कुछ ठीक रहे इस हेतु देश के वोट कबाड़ू राजनीतिक दलों से देश को बचाना होगा। हिंसा उन्हीं राजनीतिक मनों की कुंठाओं का परिणाम है। ए.ओ.ह्यूम से ऐतानिया माइनों तक देश ने बहुत सहा है, देखा है।

हम जानते हैं कि भारत में निवास करने वाले नागरिक स्नेह से निवास करते थे। समूचे विश्व के कल्याण हेतु विचार करते थे। वसुधैव कुटुम्बकम की कामना से विश्व को संदेश देते थे। मगर भारत पर जब से विदेशी आक्रान्ताओं ने आक्रमण किये, विशेषकर मुगलों एवं यूरोपियों ने तब से धर्म परिवर्तन कर लेने वाले लाखों लोगों में से कुछ लोगों ने अपने आप को आक्रमणकारियों की मानसिकता से जोड़ लिया। इस मानसिकता से देश को बाहर निकालना होगा। हालांकि भारत में आज भी सभी धर्मों के अधिकांश नागरिक 8वीं सदी से पूर्व एक जैसी धर्म व्यवस्था को जीने के आदी रहे हैं और इस विशेष जीवन पद्धति का नाम दुनिया में हिन्दू नाम से जाना जाता है। धर्म का नामकरण कुछ भी हो जाये, जीवन पद्धतियाँ परिवर्तित नहीं होती है, पुरखे परिवर्तित नहीं होते हैं। आज भी हमारे इस्लाम धर्म को मानने वाले भाई पवित्र स्थल मक्का को जाते हैं तो दुनिया भर से आये लोगों द्वारा उन्हें हिन्दी या हिन्दू के नाम से ही सम्बोधित किया जाता है। हमारे पुरखे साझा हैं, यह भाव सभी को बताना होगा, समझना होगा और समझाना होगा।

आज भारत शिक्षित हो रहा है। हमें बच्चों को सत्य बताना चाहिए अन्यथा वह आप पर भरोसा नहीं करेगा। उन्हें बताइये कि आक्रान्ताओं और राष्ट्र पुत्रों का अंतर। विशेषकर नई पीढ़ी के युवाओं को यह समझना होगा कि 8वीं सदी में भारत पर मौहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। 11वीं सदी में मौहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। 11वीं सदी में ही मौहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर आक्रमण किया। 14वीं सदी में फिरोजशाह तुगलक ने भारत पर आक्रमण किया। 16वीं सदी में औरंगजेब ने भारत की संस्कृति और सभ्यता को बड़ा नुकसान पहुंचाया। यह आक्रान्ता विदेशी थे, इनका भारत के मुसलमानों से कोई सम्पर्क नहीं था। अकबर महान सहित ऐसे लोग आक्रांताओं की श्रेणी में माने जायें। ये साम्राज्यवादी इरादे से भारत आये थे। भारतवंशी अब्दुल हमीद, अशफाकउल्लाह या झांसी के तोपची गोश खां, यह अंतर देश को समझना होगा और नई पीढ़ी को भारतीयों और विदेशियों के अंतर को समझाना होगा।

सरदार पटेल की सनातन मान्यता एक राष्ट्र, एक जन के सिद्धांत को पुनः प्रतिपादित करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत देश के समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता निरूपित करने की व्यवस्था की गई, इसे पुष्टि प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे सभी धर्मों में समानता का भाव जागृत हो।

संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर द्वारा संविधान के मूल पाठ में सैक्यूलर शब्द को शामिल न करने का औचित्य समझा जा सकता है, किंतु पंथ निरपेक्षता के नाम पर तुष्टिकरण का रथ तेजी से चलता रहा। 1976 में आपातकाल का दुरूपयोग करते हुए सैक्यूलर या पंथ निरपेक्षता शब्द समाहित करने से पंथ निरपेक्षता शब्द अपनी गरिमा खोकर अपशब्द बन गया है। देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा अहमद बनाम शाहबानो, जॉर्डन बनाम चोपड़ा, सरला मुदगल बनाम भारत संघ के तीन-तीन मुकदमों में उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार को सचेत करके समान नागरिक संहिता कानून को रचना करके लागू करने में स्वयं महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा उसके औचित्य का समर्थन करके से अधिनियमित करने का आग्रह करने के बावजूद समान नागरिक संहिता को आज तक क्यों लागू नहीं किया गया।

आज पूरे देश में सद्भाव बिगाड़ने की समस्यायें हैं, उनका समाधान शीघ्र करना चाहिये। चाहें वह कश्मीर की समस्या हो, चाहे बांग्लादेश की। अवैध नागरिकों की समस्या, चाहे राम जन्म भूमि का प्रश्न हो, चाहे राम सेतु तोड़ने की घृणित मानसिकता हो या चाहे आतंकवादी छदम वेश में किसी धर्म से अपना नाता जोड़ लेते हों, ऐसी तमाम समस्याओं से देश को मुक्ति दिलाने का एकमात्र रास्ता है, सख्त कानूनी व्यवस्थायें देश में लागू हों एवं नागरिकों के मनो में यह स्पष्टता हो कि भारत राष्ट्र पर आक्रमण करने वाले विदेशी, चाहे किसी भी धर्म के हों, वे अक्रांता हैं और उनके द्वारा आहत किये गये या तोड़े गये तमाम सांस्कृतिक स्थलों की पुनर्स्थापना हो और आम व्यक्ति के मन में यह धारणा बलवती हो कि भारत में सभी नागरिक समान हैं और देश के विकास, उन्नति और वैभव के लिए सबका साथ-सबका विकास, इस मंत्र को धारण करते हुए भारत को पुनः सारी दुनिया में मजबूती प्रदान करने मे प्रयासरहत रहेंगे। मैं सदन और सभा से एक आग्रह करूँगा कि अपनी राजनैतिक कुंठाओं से बाहर निकल कर देश हित में काम करें और स्पष्ट नीति पर काम करें ताकि हम इन समस्याओं से शीघ्र निज़ात पा सकें।

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): Madam, thank you for allowing me to respond. I have heard all the speakers. It is a matter of great concern to all of us in this House. Many of you have made very moving speeches and I have no doubt that the quality of your interest across party lines will lead to a change in the way we approach this vast problem of violence against women and children. Across the board, these are the common concerns that you have expressed. They are: the patriarchal mindset of society, the absence of the implementation of stringent laws, the delays in the completion of trails, low conviction rate, the lack of expeditious dealing with complaints, the need to check the child sex ratio imbalance, increasing safety by increasing surveillance in public places and vehicles, dealing with the heinous crimes committed by adolescent offenders, providing toilets for women in rural areas and bringing about social awareness. Many of you have given data on the crimes being committed and the low conviction rates .

I have been a Minister for the last two months and this subject was taken up by me on the day I joined. In the beginning of my response I would like to take you through the various laws that we have in different ministries that have risen to this challenge of curbing these vicious crimes

against women and children.

The Criminal Law Amendment which came into force on 3rd February, 2013, which has enhanced punishments for crimes such as rape, sexual harassment, stalking, voyeurism, indecent verbal and physical gestures and which has changed various sections of the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, the Indian Evidence Act and the Protection of Children from Sexual Offences Act.

The Prevention, Prohibition and Redressal of Women at Workplace Act, 2013 which came into force on December 9, 2013 which insists that all workplaces with more than 10 workers has to have an internal complaints committee.

The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 which addresses sexual abuse and exploitation of children and provides for child friendly procedures for reporting, evidence and investigation of such crimes.

The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, the Dowry Prohibition Act, 1961, the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 are some of the Acts brought out by the Ministry for Women and Children over the years.

However, all of you have voiced a common concern for faster trials and fast track courts. The Justice J.S. Verma Committee made no recommendations on how to do this. Section 309 of the Cr.P.C. has been amended to fix a time limit of three months but more changes are needed to bring in time bound trials. The NDA Government, under Shri Vajpayeeji, had brought in fast track courts for different issues. Mysteriously, they have been allowed to become inactive in the last so many years.

There are some other concerns that need to be redressed. I will use this forum to address other wings of the Central and State Governments. Consensual rape is a grey area and we need to review Section 375 and gangrape under Section 376 of the IPC.

We have to put in a witness and victim protection programme as other countries have because, out of fear, witnesses recant or disappear.

The current provisions relating to perjury are also very weak due to which the accused and their families put pressure on the victims or witnesses to recant their statements.

The Child Marriage Act needs to be taken more seriously and tightened. Last year only 222 cases were detected.

The registration of placement agencies, changes to the existing child labour laws to recognise the trafficking of children are also required.

We need to tighten mechanism to trace and investigate the cases of missing children.

Though this Ministry is one of the many in Government that is faced with these problems, I would like to tell you about my approach.

I believe that we need to divide the work of the Ministry to tackle the problem into three different compartments that are protection, confidence building and the hope of economic independence and infrastructure.

Under protection, this is what we, in this Government, have devised: In order to address any legal loopholes that may come under other laws, I had asked the High Level Committee on the Status of Women, 2014, to prepare a list of laws that need working on. They have done so. We will go through each one of them and see how we can provide a legal circle of protection.

However, that in itself, as all of you have rightly pointed out, is not enough. Almost all of you have asked for quick response mechanisms. So we are making a one stop crisis response centre for all crimes against women. This will be put in every district and will have attached to it a panel of police people, lawyers, a trained 24 hours caretaker, nurses, counsellors and a rescue vehicle.

From the minute a woman complains, she will come in or be brought in, and the machinery of attending to her case on the medical to the legal and temporary shelter will be set in progress. This includes every kind of case from eve teasing to rape and domestic violence.

Thirdly, we have also had a series of meetings on how to establish an All India Helpline for Women. It exists in Delhi and Gujarat but it needs to work throughout India. This should be in place in the next few months.

How will these help? If a potential criminal knows that a woman has access to women-friendly justice, he will be less ready to harass and hurt her. The victim needs access to justice and these two systems aim to provide it.

Under confidence building, we need education and employability.

I have proposed that under the existing Sabla Scheme, we add two hours of learning to each school and pay the teachers extra. The girls will be taught three types of education: how to negotiate the world around them: banks, insurance, doctors, schemes, officers to approach, etc.; legal rights; and health of their bodies: how to understand what infections are, what early marriage does to the body, etc.

My officers are working on the scheme as we speak and will converge with the Education Ministry in order to start these classes for 11 year olds and above. These classes are not just for those in school. Non school going girls will be encouraged to join them as well.

Regarding employability, while there is a network of IITs in India, these are male-oriented. There are few classes for women and these are mainly in the sewing, typing rage. What I would like to start is for women, centres of excellence that teach everything from plumbing, masonry to anything that is needed to give the woman the ability to stand alone. I am looking for CSRs, partners, grants. If any of you who have spoken and those who would have like to speak are serious about this, I would request you to put your MPLADS money into these centres when and where they come up. The Prime Minister is very keen on skill building and a large programme for the same is being worked out.

Protection is not just of the law. It also happens when we create infrastructure for women. Not just of schools and colleges but in their day-

to-day lives. Of these, the most important is toilets. We plan, as part of the new Anganwadi Schemes in which a women's community centre is to be put up, to make village toilets that adjoin these centres, making them caste and class neutral. We already have the design ready to proceed. Toilets, which is what the Prime Minister accentuated during his first speech, will go a long way in giving protection not just against random violence but increasing the health of these women.

Other issues that are being worked out with other Ministries are sanitary towel distribution, well run and accessible both abortion and delivery centres, putting separate and detailed information about women's health into medical colleges. I am told that the NCERT under the HRD Minister is putting women's issues into their text books. This is a very welcome measure.

Our Government has recently approved an amendment to the Juvenile Justice Act in which Juvenile Justice Boards will decide whether the perpetrator of a heinous crime deserves to be punished as an adult and if so, he will be tried in adult courts.

I would like your support also in increasing the powers of the National Commission for Women. Violence is of many kinds, and thousands of complaints that come to the Commission are from women whose superiors have destroyed their careers because they would not submit to their sexual advances, for instance. They have nowhere to go as even today very few workplaces have, in spite of the law, put in Complaint Committees. This includes government offices across India. Thousands of complaints come in weekly but the Commission needs the ability to investigate, even to call the accused to the commission and then recommend punishment. In the absence of this, it has become a token Commission, as Shrimati Poonam Mahajan pointed out. It needs to be recast.

There are two things the Prime Minister has placed his attention on, and they are: the malnutrition of girls and the sex ratio decline and the education of girls. Accordingly, the Finance Minister in his Budget announced the *Beti Bachao*, *Beti Padhao* campaign. This goes across Ministry lines. Four Ministries have converged to finalise a programme that will be taken up in the 100 worst districts of India in order to see whether concerted effort can bring both sex ratios on par and get more girls into school.

Shri Mann has given me an interesting idea of how one Deputy Commissioner combated the sex ratio problem and won. I would incorporate this idea in the plans we are making for these districts. If any of you have any success stories that can be replicated, please feel free to send them to me. The Kanyashree girl child programme started in West Bengal pointed out by my colleagues Ratna De Nag and Kakoli Ghosh Dastidar is an excellent idea and we could look at that as well. Let us look at why the sex ratio is skewed. It it because of the insecurity of parents, the thought of dowry, the inferior education that they expect for their girls, the lack of safety? The Beti Bachao Programme intends to work on these issues in the selected districts.

Regarding malnutrition, the ICDS or Anganwadi based programme has been in practice for 40 years. It has been allowed to deteriorate to a point where it helps no one. The Anganwadi workers have no clear direction. The food is often stolen. Some of it is ill thought of and brings no nutrition. The crÃ¨ches are in disrepair if they exist at all. The supervisory posts are mostly empty and it has simply become another MNREGA. In order to repair this, I called a meeting of all the Secretaries of the Department from the States; and they have come in with very useful suggestions. In the next month, I will begin to implement them. If we can train the Anganwadis, give them a straight jacketed job to do and use this huge network of paid women village workers in a proper manner, we may be able to measure the decrease in malnutrition in girls and in pregnant women in a few years.

Regarding adoption, which is part of the new JJ Act, and the vast numbers of children in children's homes which, in some parts, are not secure and brutalise children, the new Juvenile Justice Act has made several novel departures. We have put in procedures that have made adoption easy and regulated in a child-friendly manner. I personally have worked on this and CARA, the adoption machinery as adoption is very close to my heart. This Act has also got provision for foster care which is new to our country and we will be launching an all India campaign urging people to take in children from homes and look after them. The State will pay. The checking system to see whether the child is happy and not misused, will be put in place.

Each one of you have made good speeches, and even those who have not spoken on the Bill, I am sure, feel just as strongly. But look into your hearts. Have you done what you could do yourselves?

Regarding direct crime, many colleagues have stated that there should be no delay in registration of FIRs in all crimes against women. The Criminal Law Amendment Act of 2013 has already mandated this. But it is for each one of you and each one of us, to see that this happens in your Constituencies. If you could ensure that in your district, the non-filing of FIRs and the harassment of women by police is punished as per the law, it would soon set the administrative machinery right.

When you have your monthly meetings with the local administration in your Constituencies, again mandated by law, meetings that are attended by MLAs and local body Chair people, you could bring up these issues and ask for the SP's report. Include women's crimes in the meeting you take with district personnel as indicators of social development.

Perhaps you could pay a call on your local Judges and request them to speed up cases.

Even more importantly, you could do what Gujarat has done. Ask your Chief Ministers to make one-third of the police force women. I had written to the Chief Ministers over a month ago. I have not had any commitment from them. But all of you could push your own States to do so. This would be a major step in ensuring protection.

Mrs. Dimple Yadavji has asked for sensitisation of police personnel. I would suggest that if the police force had 33 per cent women, it would not take long for all men in and out of the police to be sensitised.

I wrote to each one of you personally, a month ago, asking you to give me your letter and commitment and land for the rape crisis centres. I have received only two replies out of 500 plus. All of you that have spoken, would you like to expedite this really important centre in your own district, have it built and monitor its progress? Have you followed up with your CMs on whether they have given land. I have talked and written to

all. I could have the centres ready by the end of the year if you would cooperate. It is not a speech that will change the women's plight. Really, this is one of the main things that could.

16.00 hrs

Many years ago, the issue rose in Parliament of child labour in the carpet industry in Banaras-Bhadohi. At that time, I formed a group called Rugmark, which I head till today, and we have rescued and rehabilitated over 16,000 children and, in effect, stopped the child labour in this carpet industry in ten years, without taking a paisa from the Government. Today, we work with the carpet industry and are an international name. Many of you have child labour issues in organised industry in your areas. What have you done to stop it, while catering to both children and their parents' income and the industry's progress together?

How much of your MPLADS funds have you spent or intend to spend on women in your constituencies? Will you pay for toilets or the anganwadi centres to make them good women community centres? How many of you will bring in companies to make the ITIs or even inspect the ITIs already existing in your districts and make sure that they include subjects for women? How many of you have started training programmes for women? How many of you have checked or encouraged martial arts programmes for girls in schools? How many of you have inspected the toilets in their schools to see if they exist or looked at the bus services to them? How many of us take in complaints from women and follow them to the end or check on the progress of missing children or look at adoption of children's homes? How many of us have put our money into working women's hostels or looked at Ministries that might fund them, as my colleague Shrimati Jayshreeben Patel had suggested?

Shri Basheer had complained about liquor shops and he is right. Women complain incessantly about how violence increases by having liquor shops in their villages. It took me all my ability to get one removed to just one kilometre away. The reason is that the State Government gets a substantial income from them. But has any State Government measured the problems that arise from these liquor shops? Perhaps a study could be done by the police themselves and the States could look at another way to earn money.

Most importantly, I would like to talk to you about bringing a change in the mindset of your community. This is where the problem lies. Thirty years ago, the Government brought about a very significant rule in the Panchayati Raj - Shri Rajiv Gandhi was responsible for this - in which 33 per cent of all women were given posts of sarpanches, municipal corporators, zila parishad members etc. This Panchayati Raj change could have been the vehicle to bring about a change for women, but it did not and it does not because we do not pay attention to it. The women sarpanches were allowed to be the weakest women whose husbands, sons, male relatives or caste heads controlled the administration of the village and the disbursement of money. A new term has come into being – pradhanpati or sarpanchpati. District administrations actually deal with these sarpanchpatis. They attend Administration meetings. None of us have complained, me either. Money has disappeared and no one can do anything against the husband and no one wants to punish the helpless wife. But even now, if we take a strong stand and say that any woman, who does not take responsibility for her village after being elected, will be removed, if we could see that all women pradhans are trained and taught regularly, then you would see a new breed of women coming up from the ground in the areas that have the most crime against women. Women social reform comes from this single root and it is a low hanging fruit for all of us.

Are these the only things that are needed for the safety of women? I would say that electricity and the availability of water would give women time. When a woman has no time from her household chores, she stands alone and vulnerable and in fear of permanent victimhood. The day is short with no electricity and she has to do almost everything from getting wood to water, cleaning to cooking and helping her husband on the land. If she has time, then she can bond with other women, form associations and social groups within the village. And social change happens through these groups. She has time to learn and teach. She has time to think of how to make herself stronger. The truth is that when schemes like Rajiv Gandhi Vidyut Yojana were put up, many Members, many of us, left it solely to State officials to implement it. In my own constituency, I have found that 400 villages declared electrified have a single standing pole. If you could make sure that various schemes for electricity are implemented or you could give solar lights in areas needed by women, you would be creating a stronger womanhood which is what we all want. If you could do these things, we might have a safer India for women and children very soon.

This subcontinent was the first to produce so many outstanding women leaders respected all over the world long after they have gone like from Sri Lanka, India, Bangladesh, Pakistan. Women, who were not afraid to lay down their lives for their country so that others may have a better life. All women and children in this country could be that strong, but it is for us to work together to create a climate in which they grow to their full potential.